बयान है। वहां के तनाव में किसी एक
कूटनीतिक तौर पर घातक साबित हो सकता है, क्योंकि
सऊदी अरब के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं।

इस यात्रा का एक

चीन के इस कमाल से हमारे विश्वविद्यालय कुछ सीखेंगे

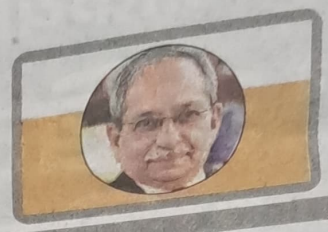

यहां स्कैन करें

हरिवंश चतुर्वेदी | महानिदेशक, आईआईएलएमबीएस

अभी एक सप्ताह पहले वैश्विक स्तर पर ग्लोबल रैंकिंग में एक धमाका हुआ है। यह धमाका नीदरलैंड्स की लीडन यूनिवर्सिटी की ग्लोबल रैंकिंग ने किया है। लीडन रैंकिंग में शीर्षस्थ 10 विश्वविद्यालयों में चीन का जे-जियांग विश्वविद्यालय नंबर एक पर आ गया है और उसने हार्वर्ड को पहले से तीसरे स्थान पर धकेल दिया है। बाकी सात स्थानों पर भी चीन के कुछ शीर्षस्थ विश्वविद्यालयों का कब्जा हो गया है। आज से 25 वर्ष पूर्व, चीन के जे-जियांग यूनिवर्सिटी शीर्ष 25 में भी नहीं थी। पिछले 25 वर्षों में चीनी विश्वविद्यालयों ने जो कुछ कर दिखाया है, इससे आने वाले दशकों में उच्च शिक्षा में भारी उतार-चढ़ाव के संकेत मिलते हैं। जरा सोचिए, हमारे अपने शीर्ष विश्वविद्यालय कहां खड़े हैं?

चीनी विश्वविद्यालयों की सफलता रातोंरात संभव नहीं हुई है। इसके पीछे उनकी सरकार द्वारा 40 वर्षों से शोध को दी गई प्राथमिकता है। चीन में ज्यादातर विश्वविद्यालय सरकार की वित्तीय मदद से चलते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर शोध-कार्यों को निर्देशित किया जाता है। चीनी विश्वविद्यालयों ने वैश्विक पत्रिकाओं में बड़े पैमाने पर प्रकाशन किए हैं। अंग्रेजी में उच्च गुणवत्ता वाले शोध-पत्रों का वैश्विक स्तर पर अधिक उल्लेख हुआ। चीनी विश्वविद्यालयों की सफलता का राज राष्ट्रीय प्राथमिकता से जुड़ा शोध-कार्य है, जैसे सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी, बायो-टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में लक्षित अनुसंधान। इसके लिए चीन ने विदेश में शोधरत अपने नागरिकों को वापस बुलाया और वैश्विक प्रतिभाओं की भर्ती की गई। चीन का रिसर्च इकोसिस्टम और पैमाना भारत की तुलना में बहुत विशाल व मजबूत है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं- बड़े विश्वविद्यालय, बड़े शोध समूह, साझा प्रयोगशालाएं और टीम-आधारित शोध संस्कृति। ये विश्वविद्यालय शोध और विकास में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर कड़ी नजर बनाए रखते हैं और उद्योगों से मिलकर योजनाओं को अंजाम देते हैं।

चीनी विश्वविद्यालयों की सफलता रातोंरात संभव नहीं हुई है। इसके पीछे उसकी सरकार द्वारा 40 वर्षों से शोध को दी गई प्राथमिकता है।

क्या चीन की सफलता से भारत कुछ सीख सकता है? इसके लिए हमें शोध को उच्च शिक्षा का केंद्र-बिंदु बनाना होगा। हमें अनुसंधान में निवेश और बढ़ाना होगा। भारत को विश्वस्तरीय रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना होगा। इसके लिए साझा प्रयोगशालाएं, शोध-परिसर और उत्कृष्टता केंद्र बनाने होंगे। ये सब काम सरकार अकेली नहीं कर पाएगी। निजी व अंतरराष्ट्रीय सहयोग द्वारा इसे मुमकिन करना होगा। शिक्षकों की वैश्विक स्तर पर भर्ती भी जरूरी है। प्रतिस्पर्द्धी वेतन, शोध में समर्थन, अकादमिक स्वायत्तता के क्षेत्रों में प्रगतिशील कदम उठाने होंगे। हमें राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से जुड़े शोध-कार्यों पर जोर देना होगा। पेटेंट, स्टार्ट-अप व सामाजिक प्रभाव पर और अधिक जोर देना होगा।

चीनी विश्वविद्यालयों की ग्लोबल रैंकिंग में सफलता से यह कतई निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए कि हमारे विश्वविद्यालयों में इसके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। बजट 2025-26 में उच्च शिक्षा पर 50,067 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया, जिसमें रिसर्च मद में आंशिक खर्च रखा गया है। इसमें राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन को 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो योजना पर भी 1,660 करोड़ रुपये वार्षिक व्यय का प्रावधान रखा गया। इसी तरह, राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 के अंतर्गत अनुसंधान उत्कृष्टता और वैश्विक जुड़ाव को भारतीय उच्च शिक्षा के रूपांतरण का एक स्तंभ माना गया है। पिछले दशक में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैकल्टी और विद्यार्थी का आदान-प्रदान और पीएचडी के संयुक्त निर्देशन पर जोर दिया गया है। वर्ष 2016 में शिक्षा मंत्रालय ने एएनएआई आरएफ रैंकिंग शुरू की थी, जिससे पिछले एक दशक में शोध और विकास के क्षेत्र में उत्साहवर्द्धक परिणाम आए हैं। इस रैंकिंग में शोध और विकास को 30 प्रतिशत वजन दिया जाता है। परंतु अभी यह स्वैच्छिक है, सिर्फ 40 प्रतिशत विश्वविद्यालय और 15 प्रतिशत कॉलेज ही इसमें भाग ले रहे हैं।

हालांकि, अनुसंधान पर अधिक कोष आवंटित किए जा रहे हैं, किन्तु वैश्विक प्रतिस्पर्धा और शोध-आधारित रैंकिंग के लिए यह नाकाफी है। भारतीय विश्वविद्यालयों को ग्लोबल रैंकिंग में बेहतर प्रदर्शन के लिए सरकार से वित्तीय समर्थन की प्रबल जरूरत होगी।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

कूटनीतिक तौर पर घातक साबित हो सकता है, क्योंकि सऊदी अरब के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं।

सिंदूर' को लेकर पाकिस्तान गाल बजा रहा है औ असलियत की जानकारी सबको है।

इस यात्रा का एक मकसद 'तेल अर्थव्यवस्था' से

चीन के इस कमाल से हमारे विश्वविद्यालय कुछ सीखेंगे

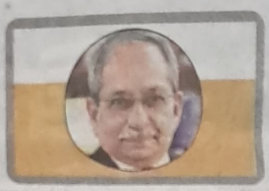

यहां स्कैन करें

हरिवंश चतुर्वेदी | महानिदेशक, आईआईएलएमबीएस

अभी एक सप्ताह पहले वैश्विक स्तर पर ग्लोबल रैंकिंग में एक धमाका हुआ है। यह धमाका नीदरलैंड्स की लीडन यूनिवर्सिटी की ग्लोबल रैंकिंग ने किया है। लीडन रैंकिंग में शीर्षस्थ 10 विश्वविद्यालयों में चीन का जे-जियांग विश्वविद्यालय नंबर एक पर आ गया है और उसने हार्वर्ड को पहले से तीसरे स्थान पर धकेल दिया है। बाकी सात स्थानों पर भी चीन के कुछ शीर्षस्थ विश्वविद्यालयों का कब्जा हो गया है। आज से 25 वर्ष पूर्व, चीन के जे-जियांग यूनिवर्सिटी शीर्ष 25 में भी नहीं थी। पिछले 25 वर्षों में चीनी विश्वविद्यालयों ने जो कुछ कर दिखाया है, इससे आने वाले दशकों में उच्च शिक्षा में भारी उतार-चढ़ाव के संकेत मिलते हैं। जरा सोचिए, हमारे अपने शीर्ष विश्वविद्यालय कहां खड़े हैं?

चीनी विश्वविद्यालयों की सफलता रातोंरात संभव नहीं हुई है। इसके पीछे उनकी सरकार द्वारा 40 वर्षों से शोध को दी गई प्राथमिकता है। चीन में ज्यादातर विश्वविद्यालय सरकार की वित्तीय मदद से चलते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर शोध-कार्यों को निर्देशित किया जाता है। चीनी विश्वविद्यालयों ने वैश्विक पत्रिकाओं में बड़े पैमाने पर प्रकाशन किए हैं। अंग्रेजी में उच्च गुणवत्ता वाले शोध-पत्रों का वैश्विक स्तर पर अधिक उल्लेख हुआ। चीनी विश्वविद्यालयों की सफलता का राज राष्ट्रीय प्राथमिकता से जुड़ा शोध-कार्य है, जैसे सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी, बायो-टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में लक्षित अनुसंधान। इसके लिए चीन ने विदेश में शोधरत अपने नागरिकों को वापस बुलाया और वैश्विक प्रतिभाओं की भर्ती की गई। चीन का रिसर्च इकोसिस्टम और पैमाना भारत की तुलना में बहुत विशाल व मजबूत है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं- बड़े विश्वविद्यालय, बड़े शोध समूह, साझा प्रयोगशालाएं और टीम-आधारित शोध संस्कृति। ये विश्वविद्यालय शोध और विकास में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर कड़ी नजर बनाए रखते हैं और उद्योगों से मिलकर योजनाओं को अंजाम देते हैं।

चीनी विश्वविद्यालयों की सफलता रातोंरात संभव नहीं हुई है। इसके पीछे उसकी सरकार द्वारा 40 वर्षों से शोध को दी गई प्राथमिकता है।

क्या चीन की सफलता से भारत कुछ सीख सकता है? इसके लिए हमें शोध को उच्च शिक्षा का केंद्र-बिंदु बनाना होगा। हमें अनुसंधान में निवेश और बढ़ाना होगा। भारत को विश्वस्तरीय रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना होगा। इसके लिए साझा प्रयोगशालाएं, शोध-परिसर और उत्कृष्टता केंद्र बनाने होंगे। ये सब काम सरकार अकेली नहीं कर पाएगी। निजी व अंतरराष्ट्रीय सहयोग द्वारा इसे मुमकिन करना होगा। शिक्षकों की वैश्विक स्तर पर भर्ती भी जरूरी है। प्रतिस्पर्द्धी वेतन, शोध में समर्थन, अकादमिक स्वायत्तता के क्षेत्रों में प्रगतिशील कदम उठाने होंगे। हमें राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से जुड़े शोध-कार्यों पर जोर देना होगा। पेटेंट, स्टार्ट-अप व सामाजिक प्रभाव पर और अधिक जोर देना होगा।

चीनी विश्वविद्यालयों की ग्लोबल रैंकिंग में सफलता से यह कतई निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए कि हमारे विश्वविद्यालयों में इसके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। बजट 2025-26 में उच्च शिक्षा पर 50,067 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया, जिसमें रिसर्च मद में आंशिक खर्च रखा गया है। इसमें राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन को 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो योजना पर भी 1,660 करोड़ रुपये वार्षिक व्यय का प्रावधान रखा गया। इसी तरह, राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 के अंतर्गत अनुसंधान उत्कृष्टता और वैश्विक जुड़ाव को भारतीय उच्च शिक्षा के रूपांतरण का एक स्तंभ माना गया है। पिछले दशक में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैकल्टी और विद्यार्थी का आदान-प्रदान और पीएचडी के संयुक्त निर्देशन पर जोर दिया गया है। वर्ष 2016 में शिक्षा मंत्रालय ने एएनएआई आरएफ रैंकिंग शुरू की थी, जिससे पिछले एक दशक में शोध और विकास के क्षेत्र में उत्साहवर्द्धक परिणाम आए हैं। इस रैंकिंग में शोध और विकास को 30 प्रतिशत वजन दिया जाता है। परंतु अभी यह स्वैच्छिक है, सिर्फ 40 प्रतिशत विश्वविद्यालय और 15 प्रतिशत कॉलेज ही इसमें भाग ले रहे हैं।

हालांकि, अनुसंधान पर अधिक कोष आवंटित किए जा रहे हैं, किन्तु वैश्विक प्रतिस्पर्धा और शोध-आधारित रैंकिंग के लिए यह नाकाफी है। भारतीय विश्वविद्यालयों को ग्लोबल रैंकिंग में बेहतर प्रदर्शन के लिए सरकार से वित्तीय समर्थन की प्रबल जरूरत होगी।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)